currency worth several thousand rupees. This had happened 1½ months back. I want to know from the Home Minister what action Government has taken against the firm on this account?

Shri Y. B. Chavan: I have no information about the foreign currency. Only certain documents were found and those documents are under scrutiny.

श्री मधु लिमये : अध्यक्ष महोदय, जिस मामले का उल्लेख किया गया यह बहुत व्यापक और मिलाजुला मामला है। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हू कि क्या उन को इस बात का पता है कि रामरतन गुप्ता साहब ने इनकम टैक्स का कानून फारेन एक्सचेंज रेगुलेशन ऐक्ट कस्टम का कानून, सेल्स टैक्स और जान्टा फौजदारी की कई धाराएं जैसे 420 आदि इन सब को तोड़ा है .....

एक माननीय सदस्य : 420 जान्टा फौजदारी की नही है।

श्री मधु लिमये : ताजीरात हिन्द, मैं गलती कर गया, तो इस की जितनी दफाएं हैं इन को तोड़ा है, तो मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उन्होंने पूरे मामले की जांच करने के लिए कोई जांच कमेटी बिठाने का विचार किया है ?

Shri Y. B. Chavan: These things are not done by appointing a committee. There are three cases which are under investigation. Whether he has committed any offence or not, I cannot give information at this stage because the matters are under investigation.

Shri S. S. Kothari: Will the hon. Minister kindly tell us on what grounds searches are carried out and whether there is any time-limit within which the document seized must be processed? Otherwise, the processing goes on taking a long time and the whole issue loses its importance.

Shri Y. B. Chavan: It should not be unduly delayed. I can accept the general proposition. But, at the same time, if there are a number of documents, technical documents, we must be a little considerate to the investigating team too.

Shri S. S. Kothari: The first part of my question has not been answered. On what basis are the searches carried out?

Shri Y. B. Chavan: Under the Act itself, in the course of investigation, if they find searches are necessary, they are empowered to make searches. These are general provisions of the Act.

Delhi Teachers' Salaries

*489. **Shri Bibhuti Mishra:**
Shri K. Anirudhan:
Shri Umanath:
Shri Viswanatha Menon:
Shri K. M. Abraham:
Shri P. P. Esthose:
Shri K. N Tiwary:
Shri N. S. Sharma:
Shri A. B. Vajpayee:
Shri Sharda Nand:
Shri Brij Bhushan Lal:
Shri Ram Singh Ayarwal:
Shri Prakash Vir Shastri:

Will the Minister of Education be pleased to state:

(a) whether Government did not accept the proposal of the Delhi Administration to increase the teachers' salaries;

(b) the reasons therefor;

(c) whether the teachers threatened to boycott the examinations; and

(d) if so, the action taken in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Education (Shri Bhagwat Jha Azad): (a) The proposal of Delhi Administration is still under the consideration of the Government.

(b) Does not arise.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि शिक्षकों के वेतन के मामले को कब तक सरकार विचाराधीन रखेगी और कब तक सरकार ने निश्चय किया है कि किस तारीख तक सरकार इस का फैसला करेगी ?

श्री भागवत झा आजाद : दिल्ली प्रशासन ने इस संबंध में सिफारिश 6 फरवरी, 1967 को भेजी है और तब से हम इस प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। क्योंकि इस प्रश्न पर और बहुत सी बातें संलग्न हैं यथा अगर शिक्षकों के वेतन बढ़ाये जाते हैं तो फिर दिल्ली प्रशासन के या दिल्ली के अन्य कर्मचारियों का क्या होगा और फिर अखिल भारतीय स्तर पर क्या होगा। इसलिए इस संबंध में देर हो रही है।

श्री विभूति मिश्र : अभी मंत्री जी के जवाब से स्पष्ट हो गया कि सरकार सोच-समझ रही है। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस संबंध में और विभिन्न स्टेटों में जो शिक्षकों की तनख्वाह है उस का पता कर के और दिल्ली का पता करके शिक्षकों की एकसी तनख्वाह सारे हिन्दुस्तान में रखने का विचार सरकार कर रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : शिक्षा आयोग की सिफारिशें इस संबंध में हमारे सामने हैं। उन सिफारिशों पर विचार हो रहा है और जब यह हमारे समक्ष आ जायगा तभी हम इस संबंध में कुछ कह सकते हैं। पिछले अप्रैल में जब शिक्षा मंत्रियों का यह सम्मेलन हुआ था तो उन्होंने शिक्षा आयोग की इन सिफारिशों को जितना स्वीकार कर लिया है उस संबंध में जो पैसे की धनराशि है उस पर विचार करना होगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : सभापति जी, मैं जानना चाहूंगा कि दिल्ली प्रशासन के ठोस सुझाव क्या हैं ? उन्होंने शिक्षकों के वेतन में कितनी वृद्धि करने का सुझाव सरकार के सामने रखा है और यदि उन के सुझाव को मान लिया तो कुल मिलाकर कितनी धनराशि खर्च होगी ?

श्री भागवत झा आजाद : दिल्ली प्रशासन ने जो सुझाव दिया है उसके अनुसार सिर्फ दिल्ली में 85 लाख 50 हजार अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी और क्योंकि दिल्ली प्रशासन में जब मान लेंगे तो केन्द्र शासित दूसरे राज्यों मे इस के अनुसार वेतन क्रम देना होगा जिसमें 36 लाख खर्च होगा। इस प्रकार सब मिलाकर 121 लाख 50 हजार रुपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होगी।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय ने बताया कि दिल्ली प्रशासन से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं, उस बारे में आपने बताया कि उन सुझावों पर अमल करने से इतनी राशि बढ़ जायगी, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि वह सुझाव क्या है ? हाई स्कूल में कितना बढ़ाया जाय, जूनियर स्कूल में कितना बढ़ाया जाय इस प्रकार की सिफारिशें क्या है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह सिफारिशें काफी लम्बी है और मैं यह बताऊं कि अगर यह सिफारिशें जो है इन को शिक्षा आयोग की सिफारिशों से मिलाकर देखें तो शिक्षा आयोग की सिफारिशों से दिल्ली के शिक्षकों का वेतन मान अधिक है। और यह सिफारिशें विभिन्न हैं, जैसे ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स के लिए हैं, प्राइमरी ग्रेड्स के लिए हैं, हायर सेकेन्ड्री स्कूल्स के प्रिंसिपलों के लिए हैं।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : ट्रेन्ड ग्रेजुएट्स को तो उन का वेतन मिल ही नहीं रहा हैं दिल्ली में।

श्री राम सिंह : मन्त्री महोदय क्या यह बतलायेंगे कि यहां पर दिल्ली के अन्दर

गैर-कांग्रेसी प्रशासन होने के कारण से यह सैलरी को बढ़ाने में देरी की जा रही है और यदि नहीं तो फिर कब तक इसके विषय में कोशिश की जायगी ?

श्री भागवत झा आजाद : ऐसी कोई बात नहीं है ।

Shri Dattatraya Kunte: Is it a fact that Government would take at least four years to come to a final conclusion?

Shri Bhagwat Jha Azad: I do not know what the hon. Member means. In this case, it was received only in February last.

श्री मधु लिमये : वैसे तो मेरा प्रश्न दिल्ली के बारे में है लेकिन वह दूसरे राज्यों और केन्द्र शासित इलाकों के लिये भी लागू होता है । मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास गैर-सरकारी स्कूलों के जो शिक्षक है उनसे कोई शिकायत प्राप्त हुई है कि सरकारी स्कूलों में उसी स्तर के और उसी गुणवत्ता या योग्यता के शिक्षकों को जो तनख्वाह मिलती है, गैर सरकारी स्कूलों में उस से कम मिलती है ? तो यह जो अन्तर है उस को कम करने के लिये सरकार दिल्ली में तथा दूसरे केन्द्र शासित इलाकों में क्या करने जा रही है और और राज्यों को क्या सलाह देने जा रही है ?

श्री भागवत झा आजाद : यह बात ठीक है कि सरकार शासित और गैर-सरकारी स्कूलों में एक ही योग्यता के शिक्षकों के वेतन मान में फर्क है । इस सम्बन्ध में दिल्ली में या सम्पूर्ण देश में क्या किया जाय इस के बारे में विस्तृत रूप से हम नहीं बता सकते है क्योंकि अभी शिक्षा आयोग की सिफारिशें हमारे सामने है, उस पर हम विचार कर रहे हैं और यह प्रश्न विभिन्न राज्यों की स्वीकृति और उन के द्वारा उस के लिए धन राशि स्वीकृत करने पर भी निर्भर करता है ।

Shri D. C. Sharma: Is it a fact that a deputation of the Government School Teachers' Association of Delhi, which is affiliated to the All India Federation of Educational Associations, met the hon. Minister of Education and also the Minister of State and made concrete suggestions to the Ministry for the upgrading of their salaries and for doing away with the disparity between private school teachers and government school teachers and for making proper arrangements for their housing and other things? If so, how long will it take the Government of India to concede their demands, or to put it in one word, to accept the Kothari Commission recommendations and apply them to Delhi and to the other Union Territories and States in India?

The Minister of Education (Dr. Triguna Sen): It is a fact that the deputation did come and met me. We discussed about their demands. My Government has all along been of the view that if we want to improve the quality of education. . .

Shri Hem Barua: Why 'my Government'? The Prime Minister alone can say that.

Dr Triguna Sen: My Ministry.

Shri D. C. Sharma: How does the hon. Member know? He may become the Prime Minister one day?

Dr. Triguna Sen: If we want to improve the quality of education and to attract the best talent available to the teaching profession, it is essential to improve the emoluments of teachers. Since we met the deputation, it has been our constant endeavour to see that this is done. We and the Ministry of Finance are at it and I hope we will be able to come to a decision very soon.